गुजरात के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले

3162. **श्री राजूभाई ए० परमार** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं ; और

(ख) किसी जिले के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मापदंड अपनाए जाते हैं ?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्र सरकार ने गुजरात में जिन जिलों का पिछड़े जिलों के रूप में पता लगाया है वे निम्न प्रकार हैं : (i) अमरेली (2) बनासकांठा (3) भडौच (4) भावनगर (5) डंग्स (6) जूनागढ (7) कच्छ (8) महसाना (9) पंचमहल (10) साबरकांठा (11) सुरेन्द्र नगर ।

(ख) औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों का पता लगाने के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार थे —(i) प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन जो इस बात पर निर्भर है कि क्या जिला प्रधानतया खाद्यान्न/नकदी फसल का उत्पादक है (अन्तर जिला तुलनाओं के लिए खाद्यान्नों तथा वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरें जहां आवश्यक हों, राज्य सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित आधार पर तय की जा सकती है), (ii) कृषि श्रमिकों का आबादी में अनुपात, (iii) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, (iv) प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे प्रकार के कार्यों में लग व्यक्तियों की संख्या, (v) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत और (vi) आबादी के अनुपात में पक्की सड़कों की लंबाई अथवा आबादी के अनुपात में रेलवे मील दूरी ।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार प्रदान किया जाना

3163. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और उत्तर प्रदेश में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिलावार संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिनको इससे लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है ;

उद्योग मंत्रालय (लघु और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनेक योजनाएं तैयार की गयी हैं । इन लोगों को रोजगार दिलाने वाली योजनाएं इस प्रकार हैं—बेकरी उत्पाद, पोहा बनाना, मसाला बनाना, पापड़ बनाना, डिटर्जेन्ट सहित कपड़ धोने और नहाने का साबुन बनाना, फलों का प्रसंस्करण और फलों का परिरक्षण, अल्यूमिनियम के घरेलू बर्तन बनाना, माचिसें और अगरबत्तियां आदि बनाना ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश भर में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 1991–92 में 1.44 लाख कारीगरों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था । किन्तु इसके जिलावार ब्यौरा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

Assistance to technocrats running small scale industries

3164. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Starred Question 133 given in the Rajya Sabha on the 16th July, 1992 and state:

(a) whether Government are evolving any formula to assist technocrats whose small scale units have been seized by

various financial institutions;

(b) what steps are proposed to ensure that personal property and savings are not seized by financial institutions from technocrats and entrepreneurs whose units have failed;

(c) what measures Government propose to take to give some relief to such entrepreneurs and technocrats; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (d) The assistance to technocrat entrepreneurs is provided with lower promoters' contribution *i.e.* at 17.5 per cent as against normal 22.5 per cent and in case there is any gap in promoters' contribution or equity, seed capital assistance in the form of soft loan is extended in eligible cases. Special attention is given during implementation and post-implementation stages. If such projects run into difficulties or show signs of sickness, need-based reliefs/concessions are given for rehabilitation. Only as a last resort, when all other measures for recovery of their dues fail, the SFCs invoke Section 29,31 and 32G of SFCs' Act (which is a Central Act). The units taken over by these institutions are handed over to the original promoter when there is one time settlement or agreement for rescheduling of the institutional dues. In case the original promoters do not settle the overdues to the Corporation, the assets are acquired by these Corporations and sold in public auctions and the proceeds realised thereof are adjusted against the dues of the institutions. In case there is still shortfall in the assets, the institutions would fall back on the collateral securities offered by the borrowing units.

Growth centres for Small Scale Industries

3165. SHRI SHANTI TYAGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have planned to develop 16 mili-growth centres for smal scale industries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what functions they are proposed to discharge and by when these centres would begin operating?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) to (c) A draft Scheme of Integrated Infrastructural Development (Including technological back-up services) for small scale industries in rural and backward areas has been prepared and included in the Eighth Five Year Plan (1992-97) proposals in pursuance of policy measures for promoting and strengthening small, tiny and village enterprises announced on 6th August, 1991. The draft Scheme is under finalisation in consultation with the concerned authorities in the Centre and State/U.T. Governments.

Phased manufacturing programme

3166. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have abolished the phased manufacturing programme;

(b) what are the incentives that are available to manufacturing units with existing phased manufacturing Programme; and

(c) whether the incentives would continue even after the abolition of Phased Manufacturing Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Under the new Industrial Policy, the system of Phased Manufacturing Programme (PMP) will not be applicable to new projects. However, existing projects with